छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक 21 (अक्टूबर – दिसंबर 2022)

ईमेलः- **chhattisgarh.sccc@gmail.com** वेबसाइटः- **www.cgclimatechange.com**

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

त्रैमासिक समाचार पत्रिका के 21वें अंक में आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है तथा इसके दुष्प्रभावों से निपटने हेतु हम सभी को कदम उठाना आवश्यक है । कार्बन उत्सर्जन को कम करने से लेकर हमारे दैनिक जीवन में सतत विकल्पों को चुनने तक, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम इसके दुष्प्रभावों से निपटने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने, अपने बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सतत भविष्य बनाने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है ।

इस अंक में हमने दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति के बारे में चर्चा की है, जो भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को **COP** 27 के दौरान प्रस्तुत किया गया। इस अंक में हमने 1979 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों के बारे में भी चर्चा की है।

हमें इस अंक में **NAFCC** परियोजना '' छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन '' की नवीनतम उपलब्धियों को साझा करते हुए भी खुशी हो रही है।

हम इस न्यूजलेटर के आगामी अंकों के लिए आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत करते हैं।

(अरूण कुमार पाण्डेय)
आई.एफ.एस.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषय–वस्तु

- एनएएफसीसी परियोजना ''छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का क्रियान्वयन
- नदी तट पर हरियाली को बढ़ावा देने के हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग का विशेष वनीकरण अभियान
- जिले में सौर सुजला योजना अंतर्गत 7398 हितग्राही लाभान्वित हुए
- LIFE भारत द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला वैश्विक जन आंदोलन
- क्या आप जानते हैं ?
- वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयास
- COP 27 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य
- भारत ने यूएनएफसीसीसी के समक्ष अपनी दीर्घकालिक कम–उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की
- समाचार शीर्षक

एनएएफसीसी परियोजना ''छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिर्वतन केन्द्र द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन फण्ड के अंतर्गत प्रायोजित पायलट परियोजना '' महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन '' का संचालन राज्य के तीन वनमण्डलों धमतरी, महासमुंद एवं बलौदाबाजार के 19 ग्रामों में किया जा रहा है। दिसम्बर 2022 की स्थिति में परियोजना अंतर्गत पूर्ण किये गये कुछ कार्यों का विवरण निम्न है :–

मेढ़ बंधी तथा भूमि समतलीकरण	801 हेक्टेयर
आद्र भूमि से गाद हटाना	22410 घन मीटर
ग्रास सीडींग / स्लिप प्लांटेशन	566500 नग
एनीकट निर्माण	15 नग
स्टॉप डैम निर्माण	05 नग
गली प्लग (ब्रश वुड चेक डेम)	4070 नग
नदीतट वृक्षारोपण	62 हेक्टेयर
परकोलेशन टैंक का निर्माण	119 नग
एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स	2350 हेक्टेयर
स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर	20 नग
स्वास्थ्य शिविर	25 नग
ड्रजरी रिडक्सन मेजर्स यथा धुँआ रहित चूल्हा एवं ब्रुम झाड़ू वितरण	514 परिवार

ग्राम– महकोनी, बलौदाबाजार वनमण्डल में एनीकट निर्माण

नदी तट पर हरियाली को बढ़ावा देने के हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग का विशेष वनीकरण अभियान

छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान 'नदी तट वृक्षारोपण' कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15 लाख 41 हजार पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 01 हजार 400 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल–फूल के पौधों से सुरभित होंगे, जो विशेष आकर्षण का केन्द्र होगा।

इनका रोपण कैम्पा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, फुलकदेई, केंदई, लीलागर नदी, महानदी, हसदेव, आगर, रेड नदी, मेघानाला, झींका नदी, मोरन, सोंढूर, बांकी नदी, गलफुला, हसदो नदी, नेउर नदी, केवई, खटम्बर, भैसुन, चूंदी, भवई नदी, बनास नदी, रांपा नदी तथा भुलू नदी आदि शामिल हैं।

इनमें से बिलासपुर वृत्त अंतर्गत में 2 लाख 89 हजार पौधों का रोपण किया गया है। इसी तरह कांकेर वृत्त अंतर्गत 4 नदियों के 19 हेक्टेयर रकबा में 20 हजार 595 पौधे तथा रायपुर वृत्त अंतर्गत 2 नदियों के 29 हेक्टेयर रकबा में 31 हजार 900 पौधों का रोपण किया गया है। इसके अलावा सरगुजा वृत्त अंतर्गत सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़ वन मंडल स्थित 12 नदियों के 1 हजार 76 हेक्टेयर रकबा में 11 लाख 84 हजार पौधों का रोपण किया गया है।

(स्त्रोत :- छत्तीसगढ़ जनसंपर्क)

जिले में सौर सुजला योजना अंतर्गत 7398 हितग्राही लाभान्वित हुए

सौर सुजला योजनांतर्गत कृषकों को बेहतर सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोलर सिचाई पम्पों की स्थापना वर्ष 2017–18 से किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये 03 एच.पी. और 05 एच.पी. क्षमता के सौर सिंचाई पम्प की स्थापना में शासन द्वारा लगभग 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में सूरजपुर जिला अंतर्गत कुल 7398 हितग्राहियों के सौर सुजला योजनांतर्गत सिंचाई पंपों की स्थापना की गई है, हितग्राही इसका लाभ ले रहे हैं।

(स्त्रोत :- छत्तीसगढ़ जनसंपर्क)

LiFE भारत द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला वैश्विक जन आंदोलन

LiFE को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित COP26 में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से "बिना सोचे समझे और विनाशकारी उपभोग के बजाय" सचेत और समझदारी से उपयोग के लिए एक जन संचलन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को एक ऐसी जीवन शैली का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है जो प्रकृति के साथ समकालिक हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली का अभ्यास करने वालों को प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में पहचाना जाता है।

प्रभाव–

अगर 2022–23 से 2027–28 में 1 बिलियन भारतीयों द्वारा सामान्य रूप जीवन शैली के विरुद्ध LiFE क्रियाओं का पालन किया जाये तो यह अनुमान लगाया गया कि LiFE क्रियाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि नीचे कुछ उदाहरणों के साथ दर्शाया गया हैरू

- ट्रैफिक लाइट / रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन को बंद करने से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है।
- सक्रिय उपयोग में नहीं होने पर चालू नल बंद करने से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है।
- खरीदारी करते समय प्लास्टिक के थैले के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने से लैंडफिल में प्रवेश करने से 375 मिलियन टन ठोस कचरे को बचाया जा सकता है।
- निकटतम ई – रीसाइक्लिंग इकाई में गैर–कार्यशील गैजेट्स को रीसायकल करने पर 0.75 मिलियन टन तक ई–कचरे का रीसायकल किया जा सकता है।
- घर में खराब भोजन को कंपोस्ट करने से 15 अरब टन भोजन को लैंडफिल में जाने से बचाया जा सकता है

(स्त्रोत :- MoEF&CC)

क्या आप जानते हैं?

सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा वर्ष 2030 तक लगभग14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत पूँजी उत्पन्न की जा सकती है।

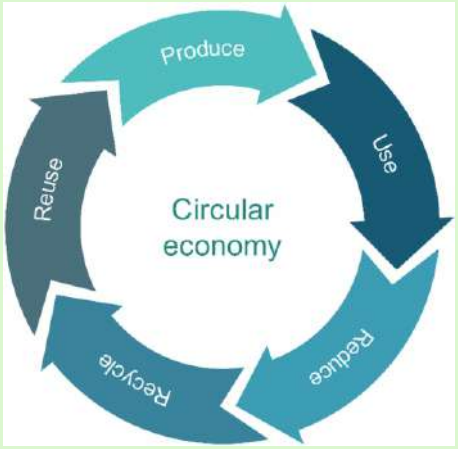

(Source:- MoEF&CC)

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयास

1979	प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन संपन्न हुआ।
1988	जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (**IPCC**) की स्थापना की गई है।
1990	**IPCC** और दूसरा जलवायु परिवर्तन पर विश्व जलवायु सम्मेलन एक वैश्विक संधि के लिए कॉल।
1991	अंतर सरकारी वार्ता समिति की पहली बैठक ।
1992	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को उसकी सिस्टर रियो कन्वेंशन के साथ हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
1994	यूएनएफसीसीसी लागू हुआ।
1995	पार्टियों का पहला सम्मेलन (**COP 1**) बर्लिन में संपन्न हुआ।
1996	**UNFCCC** सचिवालय को स्थापित किया गया सम्मलेन के तहत कार्रवाई का समर्थन करने के लिए ।
1997	क्योटो प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से दिसंबर में **COP3** में अपनाया गया है। प्रोटोकॉल कानूनी तौर पर विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के लिए बाध्य करता है।
2001	मराकेश समझौते को **COP7** में अपनाया गया। यह क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के नियमों का विवरण देता है।
2005	क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की पहली बैठक (**MOP 1**) मॉन्ट्रियल में हुई।
2007	आईपीसीसी की चौथी असेसमेंट रिपोर्ट जारी।
2009	कोपेनहेगन समझौते के ड्राफ्ट को **COP15** में कोपेनहेगन में तैयार किया गया। देशों ने बाद में उत्सर्जन में कटौती की प्रतिज्ञा या शमन कार्रवाई की गैर–बाध्यकारी प्रतिज्ञा प्रस्तुत की।
2010	**COP** 16 में कैनकन समझौते का मसौदा तैयार किया गया तथा **COP** द्वारा बड़े पैमाने पर इसे स्वीकार किया गया।
2011	एन्हांस्ड एक्शन के लिए डरबन प्लेटफॉर्म ड्राफ्ट को तैयार किया गया तथा COP द्वारा **COP17** में इसे स्वीकार किया गया।
2012	क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन सीएमपी द्वारा सीएमपी 8 में अपनाया गया। संशोधन में क्योटो प्रोटोकॉल के annexure I पार्टियों के लिए नई प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
2013	COP 19 नवंबर माह में पोलैंड के वारसॉ में आयोजित किया गया।
2014	COP20 दिसंबर माह में लीमा, पेरू में आयोजित किया गया।
2015	COP21 या CMP11 दिसंबर में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया।
2016	COP 22 मोरक्को के माराकेश में आयोजित किया गया।
2017	COP 23 फिजी द्वारा आयोजित किया गया तथा बॉन, जर्मनी में यूएनएफसीसीसी सचिवालय के मुख्यालय में आयोजित किया गया।
2018	**COP 24** का आयोजन केटोवाइस, पोलैंड मे हुआ।
2019	**COP** 25 मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था।
2021	**COP 26** ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था।
2022	COP 27 शर्म अल शेख, मिस्र में था।
2023	COP 28, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा। यह संयुक्त अरब अमीरात में होगा।

स्रोत – United Nations Framework Convention on Climate Change

COP 27 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कॉप 27 में आज भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्होने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की घोषणा की थी। एक वर्ष के भीतर भारत ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन संक्रमण वाले मार्गों को इंगित करते हुए अपनी लंबी अवधि की कम उत्सर्जन वाली विकास रणनीति प्रस्तुत की है।

हमारे 2030 के जलवायु लक्ष्यों में महत्वाकांक्षा की वृद्धि संबंधी आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने अगस्त 2022 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अद्यतन किया था। हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, ई–मोबिलिटी, इथेन०ल मिश्रित ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नए दूरगामी कदम उठाए हैं।

हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) जैसे कार्रवाई और समाधानोन्मुख गठबंधनों के माध्यम से मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये दोनों ही गठबंधन भारत द्वारा प्रारंभ और पोषित किए गए हैं।

यह विश्व कल्याण हेतु सामूहिक कार्रवाई के हमारे लोकाचार का प्रमाण है।

1.3 बिलियन लोगों का घर भारत, विश्व भर के संचयी उत्सर्जन में अब तक अपना योगदान 4 प्रतिशत से कम होने और हमारा वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई होने की वास्तविकता के बावजूद इस दिशा में विकट प्रयास कर रहा है।

सुरक्षित ग्रह के भारत के विजन के केंद्र में एक ही मंत्र है– लाइफस्टाइल फ०र एनवायरमेंट, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क०प 26 में हमारे राष्ट्रीय वक्तव्य के अंतर्गत सामने रखा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव महामहिम एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ को ल०न्च किया था।

विश्व को नासमझी भरे और विनाशकारी खपत वाले रवैये में आमूल–चूल बदलाव लाकर सोच–समझकर और उद्देश्यपूर्ण उपयोग का रवैया अपनाने की आवश्यकता है। हम इस पृथ्वी ग्रह के ट्रस्टी हैं। हमें इसे ऐसी स्थायी जीवन शैली के माध्यम से पोषित करना चाहिए, जो संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती हो और कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करती हो।

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र और जीवंत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अनुकरणीय नेतृत्व की दिशा में प्रयासरत है, और वैश्विक समुदाय को व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय–आधारित कार्यों के लिए मिशन लाइफ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है।

(स्त्रोतः पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार)

भारत ने यूएनएफसीसीसी के समक्ष अपनी दीर्घकालिक कम–उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की

भारत ने आज 27वें पार्टियों के सम्मेलन (कॉप27) के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) के समक्ष अपनी दीर्घकालिक कम–उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, ने दीर्घकालिक कम–उत्सर्जन विकास रणनीति का शुभारंभ किया। कॉप 27 6–18 नवंबर, 2022 तक मिस्र के शर्म–अल–शेख में आयोजित किया जा गया।

रणनीति की मुख्य विशेषताएं हैं–

1. ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जीवाश्म ईंधन से अन्य स्रोतों में बदलाव न्यायसंगत, सरल, स्थायी और सर्व–समावेशी तरीके से किया जाएगा।

2. जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रणय इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ाने का अभियान और हरित हाइड्रोजन ईंधन के बढ़ते उपयोग से परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करने, 20 प्रतिशत तक इथेनॉल का सम्मिश्रण करने एवं यात्री और माल ढुलाई के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों में एक सशक्त बदलाव लाने की आकांक्षा रखता है।

3. शहरीकरण की प्रक्रिया हमारे वर्तमान अपेक्षाकृत कम शहरी आधार के कारण जारी रहेगी। भविष्य में स्थायी और जलवायु सहनीय शहरी विकास निम्न द्वारा संचालित होंगे– स्मार्ट सिटी पहलय ऊर्जा और संसाधन दक्षता में वृद्धि तथा अनुकूलन को मुख्यधारा में लाने के लिए शहरों की एकीकृत योजनाय प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग कोड और अभिनव ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तेजी से विकास।

4. श्आत्मनिर्भर भारतश और श्मेक इन इंडियाश के परिप्रेक्ष्य में भारत का औद्योगिक क्षेत्र एक मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। इस क्षेत्र में कम–कार्बन उत्सर्जन वाले स्रोतों को अपनाने का प्रभाव– ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच और रोजगार पर नहीं पड़ना चाहिए।

5. भारत का उच्च आर्थिक विकास के साथ–साथ पिछले तीन दशकों में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है। भारत में जंगल में आग की घटनाएं वैश्विक स्तर से काफी नीचे है, जबकि देश में वन और वृक्षों का आवरण 2016 में कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन का 15 प्रतिशत अवशोषित करने वाला शुद्ध सिंक मौजूद है। भारत 2030 तक वन वृक्षों के आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषण की अपनी एनडीसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के मार्ग पर है।

6. निम्न कार्बन विकास मार्ग को अपनाने में नई प्रौद्योगिकियों, नई अवसंरचना और अन्य लेन–देन की लागतों में वृद्धि समेत कई अन्य घटकों की लागतें शामिल होंगी। हालांकि, विभिन्न अध्ययनों पर आधारित कई अलग–अलग अनुमान मौजूद हैं, लेकिन ये सभी आम तौर पर 2050 तक खरबों डॉलर की व्यय–सीमा में आते हैं।

(स्त्रोतः पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार)

समाचार शीर्षक

रायपुर में राज्य का पहला डापलर राडार, दिसंबर से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी

सिटी रिपोर्टर, रायपुर

क्यूमोलोनिंबस क्लाउड यानी मौसम के स्थानीय प्रभाव व लोकल सिस्टम से बने बादलों के कारण कहीं भी और कभी भी अचानक बारिश कराने वाले बादलों की जानकारी अब एक-दो घंटे पहले ही मिल जाएगी। कहां और किस जगह पर इस तरह के बादल बनेंगे और उससे कहां बारिश हो सकती है। दो घंटे पहले का पूर्वानुमान छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाता। रायपुर में लगने वाले डापलर राडार से मौसम विभाग के पास अब यह सुविधा मिल जाएगी कि वे एक-दो घंटे का भी पूर्वानुमान जारी कर सकते हैं।

10 करोड़ की लागत से तैयार होगा पूरा सेटअप

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में मंगलवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली के बीच डॉप्लर राडार की स्थापना के लिए अनुबंध हुआ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इसके लिए जमीन दी है और स्थापना की लागत तथा परिचालन व्यय भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय करेगा।

कृषि के लिए उपयोगी होगा राडार

कृषि विवि रायपुर के कृषि मौसम विज्ञान केंद्र विभाग के विभागाध्यक्ष डा. जीके दास ने बताया कि यह राडार कृषि के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। फसलों के संबंध में किसानों को आगाह किया जा सकेगा। बारिश, हवा की रफ्तार, तूफान इत्यादि की जानकारी समय रहते मिलने पर किसानों को सुरक्षा के उपाए करने का पर्याप्त मौका मिलेगा।

इन पड़ोसी राज्यों में लगा है रडार

पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के भोपाल के अलावा दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अगरतला, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना समेत अन्य शहरों में डाप्लर रडार लगे हैं। भारत में कुल 33 डाप्लर रडार लगे हैं।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक आएगी क्रांति, बनेगा दुनिया की आवाज : मोदी

भारत ऊर्जा सप्ताह में पीएम ने निवेशकों को दिया न्योता

बीते नौ वर्षों में हुए ये बड़े बदलाव

11 राज्यों में 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल '£20' की बिक्री शुरू

2030 तक एक राष्ट्र एक ग्रिड के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा हमारे पास होगा

वायो एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहे

आईएमएफ रिपोर्ट में भारत का बोलबाला

घरेलू उत्पादन को बढ़ाया देने पर जोर

तैयारी • 15 दिन में गोबर पेंट मेनुफेक्चरिंग मशीन लगाने की तैयारी, नए सरकारी निर्माण में इसी का उपयोग

गोबर पेंट बनाने उद्योग भी लगाएंगे प्रोसेसिंग प्लांट

भास्कर न्यूज़ | रायपुर

सरकारी दफ्तरों और नए निर्मित भवनों में गोबर पेंट का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। गोबर से पेंट बनाने के लिए रायगढ़ में दो गोठानों को चिन्हांकित किया गया। पिछले साल जून में ही प्रक्रिया शुरू की गई है, इसकी यूनिट नहीं लग सकी। अब 15 दिनों में यूनिट लगाकर पेंट निर्माण शुरू करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पंचायत स्तर पर लोग कह रहे हैं कि सरकारी भवनों में पेंट लगाने की अनिवार्यता के कारण अभी रायपुर से खरीदकर लगाना पड़ रहा है। 20-20 बाल्टी लाकर यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी यह पेंट रायपुर और कांकेर में ही बन रहा है।

गोबर से बने पेंट का उपयोग अनिवार्य: रायपुर से खरीदकर कर रहे हैं इस्तेमाल

दरअसल गोबर पेंट का इस्तेमाल लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, आरईएस सहित पंचायत स्तर सभी विभागों में इसी पेंट का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। नवरंगपुर सहित आसपास कुछ गांवों में गोबर पेंट इस्तेमाल करने के लिए कहा गया तो वे रायपुर से लाकर इसका उपयोग किया। हालांकि पीडब्ल्यूडी, नगर निगम जैसे दूसरी एजेंसियों के ठेकेदार गोबर पेंट नहीं मिलने पर सामान्य पेंट उपयोग करते हैं।

15 दिनों में गोबर पेंट प्लांट लगकर हो जाएगा तैयार, तेजी से चल रहा काम

जिला पंचायत के अफसरों का कहना है कि 15 दिनों में गोबर पेंट बनाने के लिए प्राकृतिक पेंट यूनिट लगानी है। इस यूनिट को राज्य बीज व कृषि विकास निगम को सप्लाई कर उन्हें यह यूनिट लगाना है। इसकी प्रक्रिया जून 2022 से चल रही है, लेकिन अब तक इसकी यूनिट नहीं लगाई जा सकी। इसमें करीब 1 करोड़ 26 लाख 90 हजार रुपए डीएमएफ से मिलना है, जिसमें खरीदी होनी है। जून में खरीदी के लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी थी, फिर भी प्रक्रिया अटकी हुई थी।

एक गोठान में यह कॉन्सेप्ट सफल होता है तो ही आगे इसे करें लागू

पुसौर ब्लॉक के सूपा गौठान और खरसिया ब्लॉक के डोंगीतराई गोठान में गोबर पेंट की यूनिट लगानी है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत के अफसरों को निर्देश दिया है कि एक गोठान में यदि यह कॉन्सेप्ट सफल होता है, तभी इसे दूसरे गोठान में भी लागू करें। इसी तरह अदानी, एमएसपी, नलवा, अम्बुजा, इंड सिनर्जी जैसे कई उद्योगों को भी कहा है कि वह भी गोबर पेंट का प्लांट लगाएं।

कांकेर और रायपुर से आता है पेंट

पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ डॉ. नरेन्द्र नायक ने बताया कि केंद्र सरकार भी गोबर पेंट को प्रमोट कर रही है। खादी इंडिया प्राकृतिक पेंट जयपुर में इसकी ट्रेनिंग हो रही है। जिले में पशु चिकित्सक और जनपद स्तर के अफसर इसकी ट्रेनिंग कर लौटे हैं। जो भी इस तरह यूनिट लगाएगा, उन्हें जयपुर के खादी इंडिया प्राकृतिक पेंट से ट्रेनिंग कराने के साथ एमओयू भी करना होगा। अभी कांकेर में एक और रायपुर में दो जगहों पर यह प्राकृतिक पेंट बन रहा है। ओडिशा के बरगढ़ में व्यापारी पेंट बना रहे हैं। तकनीक सीखने के लिए स्थानीय पंचायत स्तर के लोग वहां गए तो संगठन ने ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। पंचायत स्तर पर पेंट के लिए गोबर पेंट का उपयोग करने कहा जा रहा है तो लोग रायपुर से खरीदकर ला रहे हैं।

सम्पादक मंडल

- श्री अरूण कुमार पाण्डेय (मुख्य संपादक)
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- श्री अभिनव अग्रहरी
- श्री राजेश टोप्पो

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19

नवा रायपुर, छत्तीसगढ

ईमेल : chhattisgarh.sccc@gmail.com

वेबसाइट : www.cgclimatechange.com